(च) चल/अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण/बिक्री ।

(छ) निर्धारिती को दीवानी हवालात में रोक रखना ।

जिन मामलों में 10 लाख रु० से अधिक की रकम बकाया है उनमें अलग-अलग मामलों की छानबीन और समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यालय में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है ताकि क्षेत्र अधिकारियों का, कारगर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए उचित मार्गदर्शन किया जा सके ।

करों की बकाया की समस्या को सुलझाने की दृष्टि से और एक दृढ नीति तैयार करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, पश्चिम बंगाल के आयकर आयुक्तों तथा अधिकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया था । इस विचार-विमर्श के परिणामत: निम्नलिखित कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाये गये हैं / अथवा उठाये जाने का विचार है :—

(1) आयकर अधिकारियों तथा कर वसूली अधिकारियों के सवर्ग को सुदृढ़ करना ।

(2) पश्चिम बंगाल कार्यक्षेत्र में अन्य कार्यक्षेत्रों से तदर्थ आधार पर अपीलीय सहायक आयकर आयुक्तों को अल्प अवधि के लिए तैनात करना ताकि बकाया पड़ी अपीलों को निपटाया जा सके ।

(3) अशोध्य मांगों को तेजी से बट्टे खाते डालने के लिए एक तंत्र तैयार करना ।

(4) पहले ही अदा किये गये करों के समायोजन, भूल-सुधार संबंधी अपीलों के निपटान और अपीलीय निर्णयों को प्रभाव में लाने संबंधी कार्य को तेजी से पूरा करना ।

(5) अपीलीय प्राधिकारियों से यह निवेदन करना कि जिन मामलों में बड़ी मांगें अन्तर्गत हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर सभी अपीलों और संदर्भ याचिकाओं को लें ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य (बजट) आयकर आयुक्तों से विचार-विमर्श करते रहे हैं ताकि उनका, इस समस्या का समाधान करने में और खास कर उन मामलों के संदर्भ में जहां बड़ी मांगें अन्तर्गत हैं, मार्गदर्शन किया जा सके ।

Price Preference for Products of Public Sector Units

5783. SHRI PILOO MODY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have decided to allow a 10 per cent price preference for the products of public sector units over those of private units in the purchase made by Ministries, Government Departments and other Public Enterprises ;

(b) if so, the reasons for giving such a price preference ;

(c) whether representations have been received in this regard from a number of private units ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) Yes, Sir. In respect, mainly of engineering goods, which are of a capital nature.

(b) The main objective of the price preference scheme is to achieve fuller utilisation of capacity set up in the public sector.

(c) and (d) Some representations have been received, which are under examination.